रविवारीय

मध्य प्रदेश की नई उड़ान और अधूरी मंजिल

'बीमारू' से भारत के संभावित विकास इंजन तक, पर असली परीक्षा अभी शेष है

डॉ. आशुतोष उपाध्याय

कभी-कभी इतिहास किसी राज्य को ऐसा विशेषण दे देता है, जिससे बाहर निकलने में दशकों लग जाते हैं. 1980 के दशक में प्रख्यात जनसांख्यिकीविद् आशीष बोस ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आर्थिक-सामाजिक स्थिति देखकर 'बीमारू' शब्द गढ़ा था. कम आय, उच्च जनसंख्या वृद्धि, निम्न साक्षरता, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएँ और सीमित औद्योगीकरण, इन सबने मिलकर मध्य प्रदेश की ऐसी छवि बनाई, जो वर्षों तक राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनी रही. लगभग चार दशक बाद प्रश्न फिर उठता है, क्या 2026 का मध्य प्रदेश अब भी 'बीमारू' है? यदि उत्तर केवल आर्थिक आँकड़ों से दिया जाए, तो जवाब स्पष्ट है, नहीं. लेकिन यदि कसौटी नागरिकों का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की समान उपलब्धता हो, तो तस्वीर कहीं अधिक जटिल है. इसलिए राज्य की विकास यात्रा को केवल वृद्धि दर के चश्मे से नहीं, बल्कि मानव विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है.

आँकड़े जो नई कहानी कहते हैं- मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रमाण है. वास्तविक त्रस्ष्ठक्क वृद्धि दर 8.04 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और अर्थव्यवस्था का आकार लगभग ?16.70 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के बाद राज्य को लगभग ?30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, यदि इनका बड़ा हिस्सा वास्तविक निवेश में बदलता है, तो मध्य प्रदेश देश के सबसे तेज़ औद्योगिक विस्तार वाले राज्यों में शामिल हो सकता है.

तालिका 1 : आर्थिक उपलब्धियाँ एक नज़र में

संकेतक	मान (2025-26)	टिप्पणी
वास्तविक GSDP	8.04%	राष्ट्रीय औसत से बेहतर वृद्धि दर
अर्थव्यवस्था का आकार (GSDP)	रु. 16.70 लाख करोड	प्रचलित मूल्यों पर
प्रति व्यक्ति आय	रु.1,69,050	2011-12 से 4 गुना+
निवेश प्रस्ताव (GIS 2025)	रु. 30.77 लाख करोड़	क्रियान्वयन निर्णायक

यह उपलब्धि संयोग नहीं है. पिछले दो दशकों में सड़क, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक कॉरिडोर, शहरी अधोसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश हुआ है. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, नए एक्सप्रेस-वे और रक्षा-विनिर्माण में बढ़ते निवेश ने राज्य की सबसे बड़ी ताकत, भौगोलिक केंद्रीयता, को आर्थिक शक्ति में बदलने का अवसर दिया है. यही कारण है कि निवेशक अब मध्य प्रदेश को केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री-बिजनेस के संभावित केंद्र के रूप में देखने लगे हैं. क्षेत्रीय संरचना में प्राथमिक क्षेत्र की 43.09 प्रतिशत हिस्सेदारी बताती है कि अर्थव्यवस्था अब भी कृषि-प्रधान है, जबकि उद्योग का हिस्सा 19.79 प्रतिशत ही है. श्रमशक्ति की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती है.

बीमारू की परिभाषा बदल चुकी है- जब 'बीमारू' शब्द गढ़ा गया था, तब भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि आधारित थी और विकास का आकलन सीमित संकेतकों से होता था. 21वीं सदी में सफलता का मूल्यांकन प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नवाचार, महिलाओं की भागीदारी, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समावेशन, इन सभी मानकों पर होता है. इन कसौटियों पर मध्य प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति अवश्य की है, लेकिन मानव विकास के कई क्षेत्रों में लंबी दूरी अभी बाकी है. इसलिए 'बीमारू' शब्द अब राज्य की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, पर यह कहना भी जल्दबाज़ी होगी कि विकास की अंतिम मंज़िल मिल गई है.

आर्थिक और सामाजिक विकास, दो अलग रफ्तारें- आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक संकेतक उसी गति से नहीं सुधर रहे. यदि उद्योग बढ़ें पर

युवाओं को रोजगार न मिले, निवेश आए पर गाँवों की आय न बढ़े, एक्सप्रेस-वे बनें पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर न पहुँचें, और शहर स्मार्ट बनें पर सरकारी विद्यालयों में बच्चे बुनियादी पढ़ना-लिखना न सीखें, तो विकास अधूरा रह जाता है. विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और विकास अर्थशास्त्रियों का अनुभव बताता है कि दीर्घकालिक समृद्धि का आधार केवल पूँजी निवेश नहीं, मानव पूँजी है. दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम तथा भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक ने पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश किया; उद्योग और उच्च आय उसके बाद आए. जहाँ मानव विकास पीछे रह गया, वहाँ आर्थिक वृद्धि भी कुछ समय बाद ठहर गई. मध्य प्रदेश आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है.

दूसरे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है?- तालिका 2 : भारतीय राज्यों के विकास मॉडल

राज्य	विकास मॉडल का आधार	मध्य प्रदेश के लिए सीख
गुजरात	औद्योगिक निवेश एवं विनिर्माण	निवेश को उद्योग में बदलने की गति
तमिलनाडु	उद्योग + तकनीकी शिक्षा कौशल, स्वास्थ्य	स्थायी औद्योगिक आधार
कर्नाटक	ज्ञान-अर्थव्यवस्था, IT, नवाचार	स्टार्टअप व अनुसंधान पारितंत्र
केरल	शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास	उच्च जीवन-गुणवत्ता

मध्य प्रदेश के सामने अवसर है कि वह इन सभी मॉडलों से सीखकर अपना विशिष्ट मॉडल गढ़े, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और मानव विकास समान गति से आगे बढ़ें.

मध्य प्रदेश 2035: विकास का नया विज़न- यदि अगले दस वर्षों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय हों, तो 2035 तक राज्य भारत के अग्रणी राज्यों में स्थान बना सकता है. इसके लिए प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाना, कृषि को मूल्य-संवर्धित एग्री-बिजनेस में बदलना, मातृ-शिशु मृत्यु दर को अग्रणी राज्यों के स्तर पर लाना, साक्षरता को 90 प्रतिशत के करीब पहुँचाना, कौशल आधारित रोजगार सृजित करना, इंदौर-भोपाल-ग्वालियर-जबलपुर-उज्जैन को ज्ञान-आधारित आर्थिक केंद्र बनाना, आदिवासी अंचलों के मानव विकास सूचकांकों में तेज़ सुधार और हरित, जलवायु-अनुकूल विकास को नीति का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा.

अब चुनौती केवल सरकार की नहीं- विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होता. उद्योग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, मीडिया, किसान, उद्यमी और युवा, सभी इस साझा यात्रा के भागीदार हैं. विश्व में जिन क्षेत्रों ने सबसे तेज़ प्रगति की, वहाँ सरकार ने दिशा दी और समाज ने उसे गति दी. मध्य प्रदेश के लिए भी यही समय है कि विकास को सरकारी कार्यक्रम नहीं, सामाजिक आंदोलन बनाया जाए.

अंतिम प्रश्न

क्या मध्य प्रदेश अब भी 'बीमारू' है?, नहीं. क्या वह विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुँच चुका है?, अभी नहीं. राज्य ने पिछड़ेपन से उभरने की लड़ाई जीत ली है; अब उसे उत्कृष्टता की लड़ाई जीतनी है, और यही दूसरी यात्रा अधिक कठिन होती है. इतिहास की शिक्षा स्पष्ट है: आर्थिक समृद्धि तब तक स्थायी नहीं होती, जब तक वह सामाजिक समृद्धि में न बदले. अंतिम लक्ष्य वह समाज है जहाँ हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए, हर युवा सम्मानजनक रोजगार, हर किसान उपज का उचित मूल्य, हर महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, तथा हर नागरिक बेहतर स्वास्थ्य और समान अवसर. राज्य का विकास इंजन पूरी गति से चल पड़ा है. आने वाले दस वर्ष तय करेंगे कि मध्य प्रदेश केवल तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में याद किया जाएगा, या उस राज्य के रूप में जिसने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का साहस दिखाया. बस यह सुनिश्चित करना होगा कि इस यात्रा में कोई पीछे न छूटे.

दस नीतिगत प्राथमिकताएँ- तालिका 3 : अगली विकास यात्रा के दस निर्णायक कदम

क्र.	नीतिगत प्राथमिकता	मुख्य फोकस
1	निवेश क्रियान्वयन आयोग	एमओयू, उद्योग स्थापना व रोजगार की त्रैमासिक सार्वजनिक समीक्षा
2	जिला रोजगार सूचकांक	हर जिले में रोजगार, कौशल व श्रम भागीदारी का वार्षिक मूल्यांकन
3	एग्री-वैल्यू मिशन	फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, निर्यात व FPO को एकीकृत बढ़ावा
4	ग्रामीण स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण	PHC में चिकित्सक, टेलीमेडिसिन व डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ
5	बुनियादी शिक्षा गुणवत्ता मिशन	कक्षा 3 तक पढ़ना-लिखना-गणना का समयबद्ध लक्ष्य
6	महिला श्रम भागीदारी अभियान	SHG, सूक्ष्म उद्योग व डिजिटल उद्यमिता को समर्थन
7	कौशल विश्वविद्यालय-उद्योग साझेदारी	उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण एवं अप्रेंटिसशिप
8	नवाचार एवं स्टार्टअप क्लस्टर	इंदौर, भोपाल आदि में अनुसंधान-नवाचार पारितंत्र
9	हरित विकास नीति	सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती
10	पारदर्शी, डेटा-आधारित शासन	सार्वजनिक डैशबोर्ड व परिणाम-आधारित प्रशासन

समान शिक्षा : महान नागरिक राष्ट्र की आधारशिला

डॉ. दिलीप सिंह

'जब समुदाय, विद्यालय और सरकार मिलकर कार्य करते हैं, तब प्रत्येक सरकारी विद्यालय उत्कृष्टता का केंद्र बन सकता है और प्रत्येक बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सकता है।' इक्कीसवीं सदी में विकास की एक नई सोच उभरकर सामने आई है, जो केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है।

'गरिमामय भारत' इसी विचार पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य की जन्मजात गरिमा, समान अवसर, स्वतंत्रता और सम्मान किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति के मूल आधार हैं। केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है; ऐसा विकास आवश्यक है जो प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने तथा सुखी और सार्थक जीवन जीने का अवसर प्रदान करे।

सन् 1949 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व के अनेक देशों को 'अविकसित क्षेत्र' बताते हुए उनके आर्थिक विकास के लिए सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। उसी समय से विकास की अवधारणा को मुख्यत: आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, आय तथा भौतिक समृद्धि के आधार पर मापा जाने लगा।

सन् 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की शुरुआत की। इसके प्रणेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. महबूब उल हक का स्पष्ट मत था कि विकास का अर्थ केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों के विकल्प और स्वतंत्रता का विस्तार करना है।

एचडीआई तीन प्रमुख संकेतकों पर आधारित है—

- स्वास्थ्य (औसत जीवन प्रत्याशा),
- जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय),
- शिक्षा (वयस्कों की औसत स्कूली शिक्षा तथा बच्चों के अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष)।

इन दोनों दृष्टिकोणों—आर्थिक विकास और गरिमा-आधारित मानव विकास—में एक बात समान है कि शिक्षा दोनों की अनिवार्य शर्त है। शिक्षा ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है और साथ ही उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने की चेतना भी प्रदान करती है।

भारत विश्व की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है। देश में लगभग 14.71 लाख विद्यालय, 24.69 करोड़ विद्यार्थी तथा 1 करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। यह शिक्षा के प्रति राष्ट्र की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। किन्तु इस विशाल व्यवस्था के पीछे अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 जुलाई, 2026 को जारी 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' (ष्ठद्बस्श्व+) 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों के स्कूल में बने रहने और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के बावजूद, कक्षा-1 में दाखिला लेने वाले केवल 51.9 प्रतिशत छात्र ही कक्षा-12 तक स्कूल में बने रहते हैं।

एएसईआर-2024 के अनुसार, कक्षा-5 के लगभग 56 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा-2 का पाठ सहजता से नहीं पढ़ पाते। लगभग 70 प्रतिशत बच्चों में बुनियादी अंकगणितीय दक्षता का अभाव है। अनेक विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। अनेक छात्र प्राथमिक स्तर की बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणना करने की क्षमता से भी वंचित हैं, जबकि अनेक बालिकाएँ केवल आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विद्यालय छोड़ देती हैं (नीति आयोग 2026)

राजनीति और धर्म का मूल जीवन का अध्यात्म है!

अनिल त्रिवेदी
अभिभाषक एवं स्वतंत्र लेखक

डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा था राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति. राजनीति और धर्म ने काल के प्रवाह में जीवन को गहराई से सजाया संवारा और सतत मानव जीवन के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियां का समाधान निकाला है. राजनीति और धर्म ने कमजोर से कमजोर परिस्थिति वाले नागरिक को भी बेहतरी के सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने का आनंदमयी साधन प्रदान किया है.आज का अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक समूह भांति भांति के रंग रूप की पताकाएं फहराकर धर्म कर्म की इतिश्री समझने लगे है.

इस तरह की ताकतें एकजुट होकर समूची दुनिया में राजनीति और धर्म के मूल स्वरूप को ही एक तरह से बदलने में लगे हैं. देश और दुनिया भर में राजनैतिक और धार्मिक नेतृत्व करने वाले अधिकांश समूहों ने राजनीति और धर्म की गहराई और मर्म को अपने मूल स्वरूप से उलट एकदम भिन्न पर लगभग पूरी तरह एक ऐसी उथली मन:स्थिति के करीब पहुंचा दिया हैं जिससे बाहर निकलना आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है. राजनीति यानि एक तरह से सत्ताकी जोड़-तोड़ का अंधा एवं यंत्रवत खेल और धर्म यानी अध्यात्म से दूर अशांति, और अकारण लोभ लालच मय असहिष्णुता की पराकाष्ठा का अविवेकी हल्ला हो गया है.यह स्थिति या परिस्थिति तो राजनीति और धर्म की मूल

राजनीति और धर्म इस जगत में जीवन की ऐसी अनोखी मानवीय गतिविधियां हैं जो जीवन काल में शांति और अशांति से परे रहकर जीवन को आध्यात्मिक साधना की दुनिया में निरंतर लेजाने का मार्ग प्रशस्त करती है. राजनीति और धर्म हमारे जीवन का क्षणिक तमाशा या कोरी हलचल न होकर इस जगत में जीवन का गहरा सनातन अध्यात्म है. जैसे जल की एक बूंद और वायु या धूल का एक कण की ताकत हमें दिखाई नहीं देती पर जगत और जीवन में जो भी कुछ घटता है वह पंचतत्व के सूक्ष्म स्वरूप के विराट साकार स्वरूप में आ जाने और पुन: मूल स्वरूप में विलीन हो जाने का अंतहीन सिलसिला ही है. राजनीति और धर्म अध्यात्म के विस्तार और संकुचित होते रहने की अनंत लहरें हैं. लहरों का आना जाना आभासी दुनिया का एक एक क्षण या कण है जिसमें जीव और जीवन रचा बसा है. यही वह मूल विचार हैं जिसे हम जीवन और जगत का अध्यात्म मान सकते हैं.

अवधारणा किसी भी तरह से नहीं मानी जा सकती है. राजनीति और धर्म दोनों ही अपने मूल स्वरूप से उलट एक भिन्न स्थिति में लगभग पहुंच गए हैं. दोनों की मूल भूमिका लोक समाज की चेतना और वैचारिक सम्पन्नता को निरन्तर आगे बढ़ाने वाली होना चाहिए. पर आज के कालखंड में दोनों ही लोकसमाज मे एक तरह से प्राय: आपसी मनमुटाव, वैमनस्य और नाहक वितण्डावाद के पोषक बनते हुए आभासित होते या दिखाई पड़ते है. इसीलिए आज राजनीति और धर्म दोनों ने देश और दुनिया में जो रूप धारण कर लिया है,उससे लोक समाज एक अत्यंत जटिल यांत्रिक भुलभुलैया में निरन्तर उलझता जा रहा है.

राजनीति एक तरह से यंत्रवत,अकारण उत्तेजित तथा उलजलूल बयान बाजी करने वाले अविचारशील व्यक्तिओं का एक बड़ा हिस्सा या जमावड़ा बनती जा रही है. जिसका कुल नतीजा निष्क्रिय भीड़भाड़ वाली या अकारण उत्तेजित भीड़ की मनोदशाग्रस्त अधिकांश मनुष्य वर्तमान समय में लगातार उलझते ही जा रहे है. लोकसमाज में सामान्य सहज विचार और विवेक का आग्रह लगातार क्षीण हो रहा है. मनुष्य जीवन को विवेक सम्मत तरिके से समस्या सुलझाने की प्रेरणा देना राजनीति का मूल काम है जिसे सत्ता की अंधी दौड़ में निरन्तर दौड़ती हुई राजनीतिक जमातों ने पूरी तरह उलट दिया है. धर्म पताका हवा में लहराते रहने मात्र से धर्म की आध्यात्मिक भूमिका मनुष्य के मन में स्वत: ही विकसित नहीं हो सकती.

धर्म मनुष्य के प्राकृतिक स्वरूप और मूल चेतना का जीवंत विस्तार है और आध्यात्मिक भूमिका की बुनियाद या आधारशिला है. धर्म मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक भूमिका का निर्धारण और विस्तार करता है. धर्म एक तरह से मानव जीवन की आचार संहिता और मनुष्य मात्र के प्राकृतिक स्वरूप को व्यवस्थित रूप में जीवन के दर्शन और आचरण में उतारने का व्यवहारिक रूप स्वरूप हैं. एक सवाल मन में यह भी उठता है कि धर्म का धर्म क्या है? क्या धर्म मनुष्य मात्र तक ही सीमित है या धर्म समूचे जगत के लिए है. जैसे हवा का धर्म निरन्तर हर कहीं मौजूद रहना है.जल का धर्म भी किसी न किसी रूप में हर कहीं भूमि और भुवन में बने रहना है. वायु और जल किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद वातावरण और जीवन के विभिन्न रूपों में चाहे वह जीव जगत हो या वनस्पति जगत हो दोनों का अस्तित्व वायु और जल के अभाव में संभव ही नहीं है.

जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी

बिहार के बाँकीपुर का उप चुनाव

ईश्वर करुण

बिहार के बाँकीपुर विधानसभा का उपचुनाव आगामी को 30 जुलाई, 2026 को है..इसके लिए नामांकन की तिथि 6 जुलाई से 14 जुलाई,2026 तक है और मतों की गिनती की तिथि 3 अगस्त,2026 है.

पटना के पास स्थित बाँकीपुर का यह चुनाव इस मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ से जन सुराज के संस्थापक और सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी का एलान किया है. 2025 के विधान सभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी नव गठित जन सुराज पार्टी से उम्मीदवारों को तो चुनाव में खड़ा किया था,लेकिन स्वयं वह खड़े नहीं हुए थे.वे 'किंग मेकर' की/ सुप्रीमो की भूमिका में रहना चाहते थे.लेकिन 2025 के चुनाव में जन सुराज को एक सीट भी नहीं मिल पायी. ऐसे में बाँकीपुर विधानसभा सीट के खाली होने पर उन्होंने स्वयं को आजमाने का निर्णय किया है. इस सीट पर एनडीए ने भाजपा के युवा उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को खड़ा कर दिया है तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी जनशक्ति जनता दल पार्टी से वीणा मानवी को खड़ा कर दिया है.राजद ने भी पिछले चुनाव में अपने उम्मीदवार को इस बार भी खड़ा किया है.इस तरह से यह एक रोमांचक चुनाव बन चुका है.पिछले बार इस चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी और 98299 वोट मिले थे, 46363 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी थीं और तीसरे स्थान पर जन स्वराज के उम्मीदवार वंदना कुमारी थीं,जिन्हें मात्र 7717 मत प्राप्त हुए थे. अन्य भी उम्मीदवार थे,जिन्हें नाम मात्र के कुछ मत प्राप्त हुए थे,हाँ नोटा को 1464 वोट मिले थे. बाँकीपुर विधानसभा का सीट पिछले तीन दशक से भाजपा के खाते में है और यह बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है.

इस विधानसभा क्षेत्र से दो कायस्थ मुख्यमंत्री- कृष्ण बल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा-बन चुके हैं,कई मंत्री बन चुके हैं और यहीं से पिछले विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले भाजपा के नितिन नवीन को अचानक से भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है.ऐसे में यह विधानसभा सीट एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट बन गया है और एनडीए से भी अधिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट बन गया है.

बांग्लादेश की सियासत में फिर शेख हसीना की दस्तक

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

बांग्लादेश एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह संकेत दिया है कि वे अपने विरुद्ध चल रहे मामलों का सामना करने के लिए बांग्लादेश लौटना चाहती है. बांग्लादेश की राजनीति का सबसे जटिल पक्ष उसकी प्रतिशोध की संस्कृति रही है. आज यदि शेख हसीना स्वदेश लौटने की तैयारी कर रही है, तो उन्हें यह भी याद रखना होगा कि उनके प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तारिक रहमान लगभग 17 वर्षों तक निर्वासन का जीवन जीते रहे. यह उस समय हुआ था जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता थी और तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज कई मामलों के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना भी थी. अब जब बांग्लादेश की सत्ता का राजनीतिक संतुलन बदल चुका है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या तारिक रहमान और उनके सहयोगी शेख हसीना के प्रति उदार राजनीतिक व्यवहार अपनाएंगे या अतीत की कटुता वर्तमान निर्णयों को प्रभावित करेगी. बांग्लादेश की राजनीति अब केवल अवामी लीग और बीएनपी तक सीमित नही रह गई है. देश में इस्लामी राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा है, जबकि 2024 के जनआंदोलन से उभरे छात्र नेतृत्व ने भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान शेख हसीना के विरोध के कारण ही बनाई है. इन सभी शक्तियों की प्राथमिकताएं और राजनीतिक लक्ष्य अलग-अलग हैं. ऐसी परिस्थिति में शेख हसीना की वापसी केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनेक राजनीतिक हितों के टकराव का केंद्र बन सकती है. कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव,युवाओं का विरोध और पाकिस्तान की साजिशों के बीच शेख हसीना की वतन वापसी बेनज़ीर

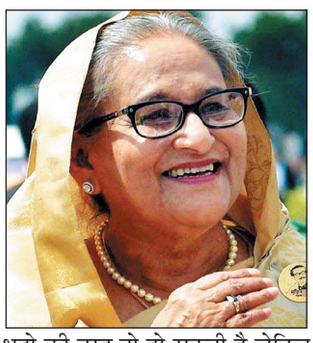

भुट्टो की तरह तो हो सकती है लेकिन उसका परिणाम बेहद जानलेवा हो सकता है,पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम सुरक्षा आशंकाओं को दरकिनार करके 2007 में स्वदेश वापसी की थी लेकिन तत्कालीन सैन्य तानाशाह ने आतंकियों से मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी. बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न है,लेकिन कट्टरपंथी ताकतें दोनों तरफ हावी है. इसी कारण शेख हसीना की संभावित वापसी को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परिपक्वता,कानून के शासन और राजनीतिक सहिष्णुता की भी परीक्षा होगी. यदि सभी पक्ष प्रतिशोध के बजाय संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते है, तो यह देश के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है. लेकिन यदि अतीत की कटुताएं वर्तमान पर हावी रही, तो बांग्लादेश एक बार फिर लंबे राजनीतिक टकराव और अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकता है. शेख हसीना पिछले डेढ़ दशक तक बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेता रही है. उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तीकरण और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की. कभी गरीब देश कहे जाने वाले बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट उद्योग, सामाजिक विकास और मानव विकास सूचकांकों में ऐसी प्रगति की कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसकी सराहना की. लेकिन विकास के इतर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया,चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगे,मीडिया की स्वतंत्रता सीमित हुई और असहमति के स्वर को दबाया गया. इसी कारण शेख हसीना को भागना पड़ा और व्यापक जनाक्रोश और राजनीतिक उथल-पुथल ने सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया. अब शेख हसीना वापस लौटकर अपने राजनीतिक दल अवामी लीग में जान फूंकना चाहती है. बांग्लादेश की सबसे पुरानी और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी अवामी लीग आज अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है. 1949 में स्थापित इस दल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र बना रहा. शेख हसीना के नेतृत्व में लगातार कई चुनाव जीतने वाली अवामी लीग ने आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तीकरण और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.